

चिन्नाम्मल और 4 अन्य

बनाम

पी.अरुमुघम और एक अन्य

17 जनवरी, 1990

[के.जगन्नाथा शेट्टी और टी.के.थॉममेन, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता - धारा 144 और आदेश 21 नियम 89-91: अदालती नीलामी बिक्री की अपास्ती - डिक्री धारक जो संपत्ति खरीदता है और नीलामी क्रेता जो डिक्री का पक्षकार नहीं है - अधिकार और उत्तरादायित्व।

प्रत्यर्था संख्या 1 ने मूल अपीलार्थी, जिसे कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, के खिलाफ वचन पत्र के आधार पर एक धन डिक्री प्राप्त की। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील की लेकिन डिक्री पर स्थगन नहीं ले सके क्योंकि वह आज्ञापित राशि के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। अपील के लंबित होने के बावजूद डिक्री को निष्पादन में रखा गया, और अपीलार्थी की संपत्तियों की दो वस्तुओं को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा न्यायालय की बिक्री में खरीदा गया था। बाद में, उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर लिया और डिक्री को अपास्त कर दिया।

इसके बाद, अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर न्यायालय की बिक्री को अपास्त करने के लिए निष्पादन न्यायालय का रुख किया कि (1) बिक्री भौतिक अनियमितताओं से दूषित थी और संपत्तियों को जानबूझकर कम मूल्य पर बेचा गया था; (2) बिक्री डिक्री धारक और नीलामी क्रेता के बीच मिलीभगत से हुई थी; उत्तरार्द्ध, पूर्व की सम्बन्धी होने के नाते, सिर्फ एक नाम ऋणदाता था; और (3) चूंकि डिक्री को उलट दिया गया था, इसलिए बिक्री को रद्द कर दिया जाना चाहिए और

पुनर्स्थापना का आदेश दिया जाना चाहिए। निष्पादन न्यायालय ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और निर्धारित किया कि डिक्री के बाद के उलटफेर पर निर्भर नहीं किया जा सकता है क्योंकि नीलामी खरीदार के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की गई थी जो मुकदमेबाजी के लिए एक अजनबी था। हालाँकि, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर लिया और अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया कि (ए) बिक्री भौतिक अनियमितताओं से दूषित हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप कम कीमत मिली थी; और (बी) डिक्री धारक और नीलामी खरीदार करीबी रिश्तेदार थे और बिक्री मिली-जुली प्रतीत होती थी। लेकिन अपील पर, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया।

अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

(1) डिक्री धारक जो अपने स्वयं के डिक्री के निष्पादन में संपत्ति खरीदता है जिसे बाद में संशोधित या उलट दिया जाता है, और एक नीलामी क्रेता जो डिक्री का पक्ष नहीं है, के बीच अंतर बनाए रखा जाता है। [84 ई]

(2) जहाँ खरीदार एक डिक्री धारक है, वह पुनर्भुगतान के माध्यम से निर्णय देनदार, लेकिन एक अजनबी नीलामी खरीदार नहीं, को संपत्ति वापस करने के लिए बाध्य है। उत्तरार्द्ध अप्रभावित रहता है और बाद में प्रत्यावर्तन या डिक्री के संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार नहीं खोता है, और संपत्ति को बनाए रख सकता है क्योंकि वह एक सदभाविक खरीदार है। यह सिद्धांत इस आधार पर भी आधारित है कि वह निष्पादित किए जाने वाले निर्णय या डिक्री की शुद्धता की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार वह मुकदमेबाजी के लिए एक आर्थिक पक्ष से अलग है। [84 ई-एफ]

जनक राज बनाम गुरदियाल सिंह, [1967] 2 एससीआर 77 और सरदार गोविंदराव महादिक बनाम देवी सहाय, [1982] 2 एससीआर 186, संदर्भित।

(3) प्रत्येक मामले में सत्य प्रश्न यह है कि क्या अजनबी नीलामी खरीदार को निष्पादन के तहत डिक्री के बारे में लंबित मुकदमेबाजी की जानकारी थी। यदि यह साक्ष्य द्वारा दिखाया जाता है कि वह संपत्ति खरीदते समय डिक्री के खिलाफ लंबित अपील के बारे में जानता था, तो उसे एक सदभाविक के रूप में कहना अनुचित होगा। वास्तव में, वह स्पष्ट रूप से एक सट्टा खरीदार है और इस संबंध में वह डिक्री धारक खरीदार से बेहतर स्थिति में नहीं है। (85 बी-सी)

छोटा नागपुर बैंकिंग एसोसिएशन बनाम सी.टी.एम. स्मिथ, [1943] पटना 325 और जमनोमल गुरदिनोमल बनाम गोपालदास, ए.आई.आर. 1924 सिंध 101, संदर्भित।

आर. राघवचारी बनाम एम.ए. पेक्किरी मोहम्मद रोथर, ए.आई.आर. 1917 मद्रास 250, खारिज किया गया।

(4) इसी तरह, नीलामी खरीदार जो एक नाम ऋणदाता था डिक्री धारक या जिसने संपत्ति का पीछा करने के लिए डिक्री धारक के साथ मिलीभगत की है, उसे भी संपत्ति को बनाए रखने के लिए संरक्षित नहीं किया जा सकता है यदि डिक्री को बाद में उलट दिया जाता है। [86 बी]

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक कानून का एक निकाय है। न्याय को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे सजा और दंड प्रदान करने वाले अधिनियम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। प्रक्रिया के कानूनों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जहां भी उचित रूप से संभव हो न्याय प्रदान किया जा सके। [87 ए-बी]

रॉजर बनाम द कोम्प्टार डी पेरिस, [1869-71] LR 3 PC. 465 पर 475 और ए.आर.अंतुले बनाम आर.एस. नायक, [1988] 2 एस.सी.सी. 602, संदर्भित।

(6) अभिलेख पर साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त है कि नीलामी खरीदार एक सदभाविक खरीदार नहीं था। इसलिए, उसके पक्ष में नीलामी की बिक्री को प्रतिपूर्ति के लिए गिरना चाहिए। न्यायालय उस निर्णय-देनदार की संपत्ति को बनाए रखने के लिए उसे सहायता नहीं दे सकता जो अन्यायपूर्ण डिक्री से छुटकारा पाने में सफल हो गया है। [87 डी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 140/1990

(एल.पी.ए. सं. 131/1987 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 8.2.89 से।)

ए.के. सेन, एन.डी.बी. राजू, के.राजेश्वरन और एन.गणपति, अपीलार्थी की ओर से।

के.आर. चौधरी और वी. बालाचंद्रन, प्रत्यर्थियों की ओर से।

**के.जगन्नाथ शेट्टी, न्यायाधिपति**

विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले से है जिसमें न्यायिक बिक्री को अपास्त करने के अपीलार्थियों के दावे को अस्वीकार कर दिया था।

अपील को जन्म देने वाले तथ्य, जैसा कि न्यायालयों द्वारा पाया गया है, संक्षेप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है।

अरुमुघम-प्रतिवादी-1 ने एक वचन पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायाधीश, सलेम से ओ.एस. संख्या 388/1968 में धन आदेश प्राप्त किया। फैसले के ऋणी सेतुरामलिंगम ने उच्च न्यायालय में अपील की लेकिन आदेश पर स्थगन प्राप्त नहीं कर सके। वह आज्ञाप्ति राशि के लिए प्रतिभूति नहीं दे सके जो कि स्थगन के लिए एक शर्त थी। अपील के लंबित होने के बावजूद डिक्री को निष्पादित किया गया था।

फरवरी 1973 में, उनकी दो संपत्तियों; (i) तीन घरों और (ii) 10.93 एकड़ भूमि को न्यायालय में बिक्री के लिए लाया गया था। उन्हें कुप्पा गौंडर, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा रुपये 7550 और रुपये 15,050 में क्रमशः खरीदा गया। अक्टूबर 1975 में, उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर अपील को स्वीकार कर लिया। वचन पत्र जो वाद का आधार था, उस पर विश्वास नहीं किया गया और उसे खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया और वादी गैर-उपयुक्त था। इसके बाद निर्णय देनदार ने बिक्री को अपास्त करने के लिए निष्पादन न्यायालय का रुख किया। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया है कि बिक्री भौतिक अनियमितताओं से दूषित थी और संपत्तियों को जानबूझकर कम मूल्य पर बेचा गया था। बिक्री डिक्री धारक और नीलामी खरीदार के बीच मिलीभगत थी। उत्तरार्द्ध पूर्व का संबंधी था और केवल एक नाम ऋणदाता था। उनका यह भी तर्क था कि चूंकि डिक्री को उलट दिया गया है, इसलिए बिक्री को अवैध किया जाना चाहिए और प्रतिस्थापन का आदेश दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने संतोषजनक साक्ष्य के अभाव में भौतिक अनियमितताओं से संबंधित सभी दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि डिक्री के बाद के उलटने पर निर्भर नहीं किया जा सकता है क्योंकि नीलामी खरीदार के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की गई है जो मुकदमेबाजी के लिए एक अजनबी था। निर्णय देनदार ने उच्च न्यायालय में अपील की और पहली बार में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सफल हुआ। विद्वान न्यायाधीश ने प्रभावी रूप से पाया कि (ए) बिक्री भौतिक अनियमितताओं से दूषित हुई थी जिसके परिणामस्वरूप संपत्तियों की कम कीमत मिली; (बी) डिक्री धारक और नीलामी खरीदार करीबी रिश्तेदार हैं और बिक्री मिलीजुली प्रतीत होती है; और (सी) न्यायालय की बिक्री के बाद उन्होंने उचित संबंध की दूसरी वस्तु को रुपये 96,000 में बेचने के लिए एक समझौता किया था। इन निष्कर्षों के साथ बिक्री को अपास्त किया गया। लेकिन अपील में, उच्च

न्यायालय की खंड पीठ ने उन सभी बिंदुओं पर परस्पर विचार व्यक्त किए हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया है।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान निर्णय देनदार की मृत्यु हो गई। उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने अब अपील की है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. सेन ने मुद्दे उठाये। हालांकि, महत्वपूर्ण और केंद्रीय मुद्दा न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार से संबंधित है कि वह डिक्री के बाद के प्रत्यावर्तन या संशोधन पर पुष्टि की गई बिक्री को दरकिनार कर दे। सवाल यह है कि क्या नीलामी खरीदार के हित को उस निर्णय देनदार के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए जो तब से उसके खिलाफ डिक्री से छुटकारा पाने में सफल रहा है। इस प्रश्न पर इस न्यायालय के दो न्यायनिर्णयन हैं: (1) जनक राज बनाम गुरदियाल सिंह और अन्य, [1967] 2 एस.सी.आर. 77 और (ii) सरदार गोविंदराव महादिक और अन्य बनाम देवी सहाय और अन्य, [ 1982 ] 2 एससीआर 186। जनक राज मामले में, अपीलकर्ता उस वाद के लिए एक अजनबी था जिसमें एक-पक्षीय धन डिक्री थी। डिक्री के निष्पादन में, निर्णय देनदार की अचल संपत्ति को बिक्री के लिए लाया गया था जिसमें अपीलार्थी सबसे अधिक बोली लगाने वाला बन गया। निर्णय-देनदार ने एक-पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया और न्यायालय ने बिक्री की पुष्टि करने से पहले इसको स्वीकार किया। इसके बाद निर्णय-देनदार ने बिक्री की पुष्टि पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि नीलामी खरीदार डिक्री धारक के साथ साजिश और मिलीभगत में था और इसलिए बिक्री की पुष्टि करने का हकदार नहीं था। निष्पादन न्यायालय ने, हालाँकि, आपत्ति को खारिज कर दिया और बिक्री की पुष्टि की, मितर, न्यायाधिपति ने उस दृष्टिकोण की पुष्टि की और कहा (79 पर):

"इसका परिणाम यह होता है कि क्रेता का स्वामित्व बिक्री की तारीख से संबंधित होता है न कि बिक्री की पुष्टि से। 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश XXI के तहत या कहीं और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह बताता हो कि बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी यदि यह पाया जाता है कि जिस डिक्री के तहत बिक्री का आदेश दिया गया था वह बिक्री की पुष्टि से पहले उलट दिया गया है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसमें कभी संदेह किया गया है कि एक बार बिक्री की पुष्टि हो जाने के बाद निर्णय-देनदार संपत्ति वापस पाने का हकदार नहीं है, भले ही वह उसके बाद उसके खिलाफ डिक्री को उलटने में सफल हो जाए। सवाल यह है कि क्या बिक्री की पुष्टि से पहले डिक्री को उलटने पर भी वही परिणाम आना चाहिए।

दोनों मामलों के बीच अंतर करने का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी-निर्णय-देनदार के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में की गई बिक्री के आधार पर अपनी संपत्ति खोना निश्चित रूप से कठिन है, जिसे अंततः बरकरार नहीं रखा गया है। एक बार हालांकि, यह माना जाता है कि वह बिक्री की पुष्टि के बाद शिकायत नहीं कर सकता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए क्योंकि ऐसी पुष्टि से पहले ही डिक्री को उलट दिया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विस्तृत प्रावधान हैं जिन्हें डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की बिक्री के मामलों में पालन करना होगा। यह भी बताता है कि कैसे और किस तरीके से ऐसी बिक्री को अपास्त किया जा सकता है। सामान्यतया, यदि आदेश XXI के नियम 89 से 91 के किसी भी प्रावधान के तहत बिक्री को रद्द करने के

लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या जब इनमें से किसी भी नियम के तहत कोई आवेदन किया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो न्यायालय के पास पुष्टि करने के मामले में कोई विकल्प नहीं होता है। बिक्री और बिक्री को पूर्ण बनाया जाना चाहिए। यदि विधायिका का इरादा यह था कि बिक्री को निरपेक्ष नहीं बनाया जाना था क्योंकि डिक्री का अस्तित्व समाप्त हो गया था, हमें आदेश XXI या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के भाग II में इस आशय के प्रावधान की उम्मीद करनी चाहिए थी जिसमें धाराएँ 36 से 74 तक हैं। (सम्मिलित) .....।“

अंत में, विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय को इस प्रकार पूरा किया (86 पर):

“..... विधानमंडल की नीति यह प्रतीत होती है कि जब तक एक अजनबी नीलामी-क्रेता को मुकदमे की किस्मत के उतार-चढ़ाव से बचाया नहीं जाता है, निष्पादन में बिक्री ग्राहकों को आकर्षित नहीं करेगी और यह उधारकर्ता और लेनदार के हितों की हानि होगी यदि बिक्री को केवल इसलिए चुनौती देने की अनुमति दी गई थी क्योंकि डिक्री को अंततः रद्द कर दिया गया था या संशोधित किया गया था। 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता निर्णय-देनदार के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करती है, जो महसूस करता है कि डिक्री उसके खिलाफ पारित नहीं की जानी चाहिए थी।“

सरदार गोविंदराव महादिक में, डी.ए.देसाई, न्यायाधिपति ने जनक राज मामले में सिद्धांतों को संदर्भित करते हुए कहा (224 पर):



"आम तौर पर, यदि नीलामी खरीदार कोई बाहरी व्यक्ति है या अजनबी और यदि डिक्री के निष्पादन पर स्थगन नहीं नगय गया था जिसके बारे में उसने खुद को उचित रूप से जांचने पर आश्वस्त किया होगा, न्यायालयी नीलामी आयोजित और बिक्री की पुष्टि और परिणामी बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने से सुरक्षा मिलेगी। भले ही वह डिक्री जिसके निष्पादन में नीलामी बिक्री आयोजित की गई है जिसे अपास्त किया गया हो। यह इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अजनबी के पक्ष में इक्विटी संरक्षित होनी चाहिए और अपील की लंबित अवधि के दौरान डिक्री के निष्पादन पर स्थगन प्राप्त कर पाने के कारण कभी-कभी निर्णय देनदार की ओर से चूक के कारण स्थिति उत्पन्न हो जाती है।"

विद्वान न्यायाधिपति ने आगे कहा:

"लेकिन क्या होगा यदि नीलामी-खरीदार स्वयं डिक्री धारक है? हमारी राय में स्थिति भौतिक रूप से बदल जाएगी और यह डिक्री धारक-नीलामी खरीदार किसी भी सुरक्षा का हकदार नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से, जब वह निष्पादन के साथ आगे बढ़ता है वह इस तथ्य से अवगत है कि एक मूल डिक्री के खिलाफ अपील लंबित है। वह इस तथ्य से अवगत है कि परिणामी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ अपील की अनुमति दी जा सकती है जहाँ अपील की अनुमति दी जा सकती है और जिस डिक्री को वह निष्पादित करना चाहता है उसे अपास्त कर दिया जा सकता है। वह धन डिक्री में निर्णय लेने वाले देनदार की आर्थिक विकलांगता का लाभ उठाते हुए डिक्री को निष्पादित करके गति को मजबूर नहीं कर सकता है और निर्णय

देनदार के पूर्ण नुकसान के लिए स्थिति को अपरिवर्तनीय बना देता है जो लड़ाई जीतता है और युद्ध हार जाता है। इसलिए, जहां नीलामी खरीदार कोई और नहीं बल्कि डिक्री धारक है जो यह इंगित करके कि नीलामी में कोई बोलीदाता नहीं है, एक नाममात्र राशि में संपत्ति खरीदता है, अर्थात्, इस मामले में रुपये 500 के लिए एक अंतिम डिक्री के लिए, मोतीलाल ने रुपये 300 में संपत्ति खरीदी, अत्याचारी स्थिति, और फिर भी एक तकनीकी रूप से वह अपनी रक्षा करना चाहता है। ऐसे नीलामी खरीदार के लिए जो कोई अजनबी नहीं है और जो डिक्री धारक के अलावा और कोई नहीं है, न्यायालय को उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए।"

जनक राज मामले में, एक अजनबी नीलामी खरीदार को संरक्षण दिया गया था मुकदमे के भाग्य के उतार-चढ़ाव के खिलाफ। एस.जी. महादिक के मामले में इस तरह का संरक्षण नीलामी खरीदार को नहीं दिया गया था जो स्वयं डिक्री धारक होता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि डिक्री धारक वाद के लिए अजनबी नहीं है। वास्तव में, वह इसलिए नहीं है क्योंकि वह उस डिक्री के खिलाफ अपील में आर्थिक पक्षकार है जिसे वह निष्पादित करना चाहता है। वह इस तथ्य से अवगत है कि आर्थिक कठिनाई के कारण निर्णय ऋणी डिक्री पर रोक लगाने में असमर्थ था। हालाँकि, वह मुकदमे के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता है जो उसने शुरू किया है। वह निर्णय देनदार की असहाय स्थिति का फायदा उठाता है और डिक्री के निष्पादन में तेजी लाता है। इसलिए, न्यायालय को उसे खरीदी गई संपत्ति को बनाए रखने के लिए अपनी सहायता नहीं देनी चाहिए, यदि बाद में डिक्री को उलट दिया जाता है।

इस प्रकार डिक्री धारक जो अपने स्वयं के डिक्री के निष्पादन में संपत्ति खरीदता है जिसे बाद में संशोधित या उलट दिया जाता है, और एक नीलामी क्रेता जो डिक्री का

पक्ष नहीं है, के बीच एक अंतर बनाए रखा जाता है। जहां क्रेता डिक्री धारक है, वह पुनर्स्थापन के माध्यम से निर्णय देनदार को संपत्ति लौटाने के लिए बाध्य है, लेकिन किसी अजनबी नीलामी क्रेता को नहीं। उत्तरार्द्ध अप्रभावित रहता है और डिक्री के बाद के उलटफेर या संशोधन से संपत्ति पर स्वामित्व नहीं खोता है। न्यायालय ने माना है कि वह संपत्ति अपने पास रख सकता है क्योंकि वह एक सदभाविक खरीदार है। यह सिद्धांत इस आधार पर भी आधारित है कि वह निष्पादित किए जाने वाले निर्णय या डिक्री की सत्यता की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार वह मुकदमे के आर्थिक पक्षकार से विशिष्ट है।

इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है और यह वास्तव में एक निष्पक्ष और उचित वर्गीकरण पर आधारित है। निर्दोष खरीदार चाहे स्वैच्छिक हस्तांतरण या न्यायिक बिक्री में किसी डिक्री या आदेश द्वारा या उसके निष्पादन में दंडित नहीं किया जाएगा। मुकदमेबाजी से अनजान सदभाविक रूप से खरीदी गई संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। विशेष रूप से न्यायिक बिक्री से उनकी पूरी पवित्रता खत्म नहीं होगी। यह कानूनी और न्यायसंगत विचारों पर आधारित एक ठोस नियम है। लेकिन यह समाख पाना मुश्किल है कि ऐसे खरीदार को ऐसे सुरक्षा क्यों दी जानी चाहिए जो डिक्री से सम्बंधित लंबित विवाद में बारे में जानता है। यदि कोई व्यक्ति डिक्री धारक और निर्णय देनदार के बीच विवाद से पूरी तरह अवगत होते हुए संपत्ति खरीदने का साहस करता है, तो उसे सदभाविक खरीदार मानना मुश्किल है। इसलिए, प्रत्येक मामले में सही प्रश्न यह है कि क्या अजनबी नीलामी खरीदार के पास निष्पादन के तहत डिक्री के बारे में लंबित मुकदमे की जानकारी थी। यदि साक्ष्य इंगित करता है कि उसे ऐसा कोई ज्ञान नहीं था तो वह एक सदभाविक होगा खरीदार होने के नाते खरीदी गई संपत्ति को बनाए रखने का हकदार होगा और संपत्ति पर उसका अधिकार डिक्री के बाद के उलटफेर से अप्रभावित रहेगा। न्यायालय को हर तरह से उसकी खरीद की रक्षा करनी चाहिए।

लेकिन अगर यह साक्ष्य से दिखाया जाता है कि वह संपत्ति खरीदने के समय डिक्री के खिलाफ लंबित अपील के बारे में जानते थे, तो उसे एक सदभाविक या खरीदार के रूप में कहने का अधिकार अनुचित होगा। ऐसे मामले में न्यायालय यह भी नहीं मान सकता कि पुनर्स्थापना के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए वह एक सदभाविक या निर्दोष क्रेता था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत कोई भी धारणा नहीं बनाई जा सकती और ऐसी कोई भी धारणा गलत और अनावश्यक होगी।

छोटा नागपुर बैंकिंग एसोसिएशन बनाम सी.टी.एम. स्मिथ और अन्य, [1943] पटना 325 में पटना उच्च न्यायालय ने इसी तरह का विचार अभिव्यक्त किया। फजल अली, मुख्य न्यायाधिपति, तत्समय, उन्होंने (327 पर) कहा था कि जहां स्पष्ट और ठोस प्रमाण है कि एक अजनबी खरीदार अपने द्वारा खरीदी गई संपत्ति के संबंध में विवाद के गुणों से पूरी तरह से अवगत था और यह भी जानता था कि डिक्री की वैधता चुनौती के अधीन थी, इस धारणा के लिए कोई जगह नहीं है कि वह एक सदभाविक खरीदार था। जमनोमल गुरदिनोमल बनाम गोपालदास और अन्य, ए.आई.आर. 1924 सिंध 101 में सिंध न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के निर्णय पर भी जोर दिया जा सकता है। जहाँ इसी तरह की टिप्पणी की गई थी।

आर.राघवचारी बनाम एम.ए. पक्किरी मोहम्मद रोथर और अन्य, ए.आई.आर. 1917 मद्रास 250 में मद्रास उच्च न्यायालय ने, हालाँकि, इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 144 सी.पी.सी. के तहत पुनर्स्थापना की मांग एक सदभाविक खरीदार के खिलाफ नहीं की जा सकती है जो डिक्री में पक्षकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री को उलटने या अपील के लंबित होने के बारे में खरीदार की जानकारी से उस नियम के संचालन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है।

हालाँकि, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में, जो व्यक्ति डिक्री के खिलाफ लंबित अपील की जानकारी के साथ न्यायालय की नीलामी में संपत्ति खरीदता है, वह पुनर्स्थापना का विरोध नहीं कर सकता है। लंबित मुकदमे के बारे में उसकी जानकारी से मामले में बहुत फर्क पड़ेगा। वह वाद के लिए एक अजनबी हो सकता है, लेकिन उसे संपत्ति खरीदने में सोचा-समझा जोखिम लेने के लिए माना जाना चाहिए और वास्तव में, वह स्पष्ट रूप से एक सट्टा खरीदार है और इस संबंध में वह डिक्री धारक खरीदार से बेहतर स्थिति में नहीं है। इसलिए उसे पुनर्स्थापना से बचाने की आवश्यकता अनुचित प्रतीत होती है। इसी तरह नीलामी खरीदार जो डिक्री धारक का नाम ऋणदाता था या जिसने खरीद के लिए डिक्री धारक के साथ मिलीभगत की है यदि बाद में डिक्री को उलट दिया जाता है तो वह भी संपत्ति को बनाए रखने के लिए संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

एक और पहलू है जो हमारी तुलना जो अब तक चर्चा की है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। रॉजर बनाम में दा कोम्प्टोयर डी' 'एस्कॉम्प्टे डी पेरिस, [1869-71] एल.आर. 3 पी.सी. 465, 475 पर लार्ड कैन्स ने इस पर जोर दिया था:-

“..... सभी न्यायालयों के पहले और सर्वोच्च कर्तव्यों में से एक यह ध्यान रखना है कि न्यायालय के कार्य से किसी भी पक्षकार को कोई चोट न पहुंचे, और जब अभिव्यक्ति "न्यायालय का कार्य" का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब केवल प्राथमिक न्यायालय, या किसी मध्यवर्ती अपील न्यायालय का कार्य, लेकिन समग्र रूप से न्यायालय का कार्य, सबसे निचले न्यायालय से जो मामले पर अधिकार क्षेत्र रखता है, उच्चतम न्यायालय तक जो अंततः मामले का निपटान करता है। यदि मैं अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं, तो यह उन सभी न्यायाधिकरणों का कर्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान

रखें कि पूरी कार्यवाही के दौरान न्यायालय के किसी भी कार्य से न्यायालय में मुकदमा करने वालों को चोट न पहुंचे।“

यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में उल्लेखित सिद्धांत भी है। यह सभी न्यायालयों का कर्तव्य है, जैसा प्रिवी कौंसिल ने माना है “उन न्यायाधिकरणों के समुच्चय के रूप में” की ध्यान रखे कि पूरी कार्यवाही के दौरान न्यायालय के किसी भी कार्य से न्यायालय में मुकदमा करने वालों को चोट न पहुंचे। उपरोक्त परिच्छेद ए.आर.अंतुले बनाम आर.एस.नायक और अन्य, [1988] 2 एस.सी.सी. 602 में 672 पर उद्धृत किया गया था। मुखर्जी, न्यायाधिपति, तत्समय, ने लार्ड कैन्स के उक्त अवलोकन का उल्लेख करते हुए कहा (672 पर):

"न्यायालय के गलती का खामियाजा किसी भी आदमी को नहीं भुगतना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तकनीकी प्रक्रिया की अनियमितताओं से नुकसान नहीं उठाना चाहिए। नियम या प्रक्रियाएं न्याय की दासियाँ हैं न कि रखैल। या न्याय के दायित्व के कारण, हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, जब तक यह न्याय प्रशासन की मानव तंत्र के भीतर है, उस गलत का निवारण किया जाना चाहिए।"

यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता न्याय की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियात्मक कानून का एक निकाय है और इसे दंड और जुर्माने का प्रावधान करने वाले अधिनियम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। प्रक्रिया के कानूनों का इस तरह से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए कि जहां भी उचित रूप से संभव हो न्याय प्रदान किया जा सके। हमारी राय में, डिफ्री के खिलाफ लंबित

अपील से अवगत होने के कारण न्यायालय की नीलामी में संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति से पुनर्स्थापना की मांग करना अनुचित नहीं है।

हमने मामले में साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मामले में जिस निर्णय देनदार की जांच की गई है, उसने कहा है कि नीलामी क्रेता डिक्री धारक का समबन्धी है। डिक्री धारक की बेटी की शादी नीलामी क्रेता के बेटे से कर दी गई है। वह साक्ष्य निर्विवाद है। साक्ष्य आगे इंगित करते हैं कि खरीद के बाद उन दोनों ने संपत्ति की दूसरी वस्तु को 96,000 रुपये में बेचने के लिए एक तीसरे पक्ष के साथ एक समझौता किया है और उस समझौते के आधार पर एक मामला लंबित प्रतीत होता है। साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि नीलामी खरीदार के पास संपत्ति खरीदने के लिए अपना कोई पैसा नहीं था। ये परिस्थितियाँ यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि नीलामी खरीदार एक सदभाविक खरीदार नहीं था। इसलिए, उसके पक्ष में नीलामी की बिक्री को प्रतिस्थापन के लिए होना चाहिए। न्यायालय उस निर्णय देनदार के संपत्ति को बनाये रखने के लिए सहायता नहीं दे सकता है जो अन्यायपूर्ण डिक्री से छुटकारा पाने में सफल रहा है।

परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को उलट दिया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश की पीठ ने निर्णय को बहाल किया जाता है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को नीलामी खरीदार को इस अपील की लागत का भुगतान करना होगा, जिसे हम 5,000 रुपये निर्धारित करते हैं।

आर.एस.एस.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

**अस्वीकरण** - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।